बिहार में विपरीत प्रवजन और सरकार की निति *मनरेगा के विशेष सन्दर्भ में*

डॉ कमलेश कुमार

पी·एच्·डी· इन अर्थशास्त्र, बी·आर·ए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर·

आमुखरू.

यह एक सर्वमान्य तथ्य हैं कि बिहार भारतीय गणतंत्र का एकमात्र ऐसा राज्य हैं जहाँ गरीबी बड़े पैमाने पर सम्पूर्ण राज्य में व्याप्त हैं। कारण भी अकाट्य तथ्यों के रूप में ;पद्ध न्यूनतम प्रतिवयक्ति आय ;पपद्ध निम्न स्तरीय कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता ;पपपद्ध भूमि का असमान वितरण ;पअद्ध भूमिहीन कृषक मजदुर परिवार कि बहुलता ;अद्ध कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ;अपद्ध औधोगिकरण का सर्वथा आभाव ;अपपद्ध शिक्षणए प्रशिक्षण एवं अन्य अनेक आर्थिकए सामाजिकए राजनितिकए सांस्कृतिक एवं सांस्कारिक अवरोधों के मौजूदगी लम्बे समय से बिहार के समग्र विकास के प्रयास को त्वरित करने के सभी उपायों को निष्फल कर देती है। राज्य अर्थव्यस्था के सभी क्षेत्रो में व्यापक शिथिलताए आधारभूत संरचनाओं की दरिद्रताए निम्नस्तरीय या गुड़ गवर्नेंस का आभाव बिहार को बीमारू राज्य के श्रेणी में खड़ा कर दिया हैं। जबकि तीव्र गति से बढ़ती आबादी बहुसंख्यक गरीब परिवार के व्यस्क सदस्यों को जीवन कि न्यूनतम जरूरतों कि पूर्ति के लिए घर.परिवार को छोड़कर रोजी. रोजगार के लाभप्रद अवसरों की खोज में प्रवजित होने को बाध्य करते हैं। परिणामतः बिहार देश का सर्वाधिक प्रवजित ;डपहतंजमद्ध श्रमिकों के राज्य के रूप में कुविख्यात हो गया हैं।

प्रवजन के मुलभुत और मौलिक कारणों के पहचान के पश्चात् जब हम बिहार से प्रवजित श्रमिकों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि व्रितानी कॉलोनी के रूप में विकसित होने से पूर्व बिहार प्राचीन काल में एक संपन्नए स्ववालम्बी और आत्मनिर्भर प्रान्त के रूप में बिकसित था। यहाँ के लोग दूसरे के लिए एक मिशाल या नमूना के रूप में विख्यात थे। लेकिन व्रितानी शासन काल में यहाँ कि अर्थव्यस्था को ध्वस्त कर लोगों को गांव.घर छोड़कर शहरो कि ओर पलायन को मजबूर कर दिया।

व्रितानी कॉलोनी के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात् यहाँ के तमाम लघु एवं कुटीर औधोगिक इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया। परिणामतः अपने.अपने स्वरोजगार में नियोजित लोग बेरोजगार हो गए और अपने मौलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर शहरों कि ओर प्रवजित होने को मजबूर हो गए। कृषि में लगे लोगों को भी बाद के बर्षों में जमींदारी व्यस्था विकसित होने पर कश्कारों रैयतों और अंततः कृषि श्रमिकों में परिवर्तित कर दिया गया और कृषि विकास के न्यूनतम उपायों को भी क्रियान्वित नहीं किये जाने पर कृषि और किसानी भी लाभकारी नहीं रह गया। बर्षा आधारित कृषि में सालोभर श्रमिकों को नियोजित कर पाना संभव नहीं हो पाया और कृषि श्रमिकों को भी शहरों कि ओर पलायन करना उनकी नियति बन गयी।

<u>प्रवजन के कारण</u>

जनगणना में प्रवजन के निम्नलिखित छह कारणों को चिन्हित किया गया हैं रू.

;पद्ध काम या रोजगारए ;पपद्ध व्यवसायए ;पपपद्ध शिक्षाए ;पअद्ध शादीए परिवार के साथए ;अद्ध जन्म के पश्चात् और ;अपद्ध नियोजन

जबकि छैव ने जनगणना कि तुलना में अधिक स्पष्टता के साथ प्रवजन के कारणों को निम्न रूप में रेखांकित किया हैं रू.

;पद्ध रोजगार के खोज में

;पपद्ध पहले से अच्छा रोजगार के खोज में

;पपपद्ध बेहतर रोजगार प्राप्त करने के लिए

;पअद्ध व्यापर करने के लिए

;अद्ध कार्यस्थल के स्थानांतरण के कारण

;अपद्ध अध्ययन के लिए

;अपपद्ध स्वास्थ्य लाभ हेतु

;अपपपद्ध शादी ब्याह

;पगद्ध अभिभावक या माता पिता का स्थानांतरण

;गद्ध अन्य

ब्छैै और छैः के द्वारा रेखांकित कारणों और बिहार राज्य कि आर्थिक सामाजिक राजनितिक शैक्षणिकए सांस्कृतिक ऐतिहासिक और मानसिक. मनोविज्ञान स्तिथियों और दशाओं ने बिहार के श्रमिकों को प्रवजित श्रमिकों के रूप में देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में अलग पहचान दिला दिया हैं। खासकर 15 नवम्बर 2000 में झारखण्ड के अलग होने पर बिहार के जो 18 जिले बिहार से झारखण्ड में शामिल किये गए उनमे बिहार ;विभाजनपूर्व बिहारद्ध के सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयों का स्थानांतरण हो गया साथ ही साथ कुल क्षेत्रफल का 40ः झारखण्ड में चला गया जबकि आबादी केवल 18ः ही जा पायी। परिणामतः विभजनोपरांत शेष बिहार आलूए बालू और बाढ़ के साथ जनसँख्या घनत्व 324 से 882 और फिर 1106 पर पहुंचकर सघन और सर्वाधिक जनसँख्या घनत्व वाला राज्य बन गया। बिहार कि इस विशेषता ने प्रवजन कि गति को तीव्र से तीव्रतर कर दिया।

निःसंदेह पिछले 15.20 बर्षों में विकास के अनेको योजनाओं परियोजनाओं को क्रियान्वित कर बिहार के विकास की गति को सम्मानजनक स्तर पर लाने का सार्थक प्रयास किया गया हैं।

जैसा की हम सभी सहमत हैं कि बिहार अर्थव्यस्था मूलतः कृषि आधारित सेवा बाहुल्य राज्य हैं। 2016 में कृषि का 23ः औद्योगिक क्षेत्र का 17ः और सेवा क्षेत्र का 60ः योगदान ळक्च् को हो रहा था।

2002 से 2007 में राज्य के औद्योगिक उत्पादों का विकास दर 0ण्38 : जबकि राष्ट्रिय स्तर 7ण्8 : था। बिहार में प्रतिव्यक्ति आय देश में सबसे कम हैं। ळक्च् का वृद्धि दर 10ण्53ः ;2018.19द्ध जबकि प्रतिव्यक्ति ळक्च् 43822 रु० ;2018.19द्ध कृषि क्षेत्र. 20ःए औद्योगिक क्षेत्र. 19ः और सेवा क्षेत्र. 61ः ;2018.19द्ध में था। गरीबी रेखा से नीचे का वर्तमान आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं हैं किन्तु 2013 में 33ण्74ः था। मानव विकास सूचकांक 2018 में 0ण्566 था। जब हम श्रम नियोजन पर विचार करे तो ;पद्ध कृषि क्षेत्र में. 56ःए ;पपद्ध औद्योगिक क्षेत्र. 8ः और सेवा क्षेत्र में 36ः हैंए 2015 के आकड़ों के आधार पर। सपष्टतः कहा जा सकता है कि कृषि पर श्रम का निर्भरता सर्वाधिक है। और परिणाम स्वरुप कृषि क्षेत्र का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। कारण केवल श्रमशक्ति की अत्यधिक निर्भरता नहीं हैं। इसके साथ साथ निम्नलिखित तर्क भी जिम्मेवार हैं रू.

;पद्ध सुनिश्चित सिचाई योजना का आभावए केवल 43ः कृषित भूमि ही सिंचित हैंए बाकि का 57ः मौसम और बर्षा पर आधारित हैं।

;पपद्ध कृषि में यंत्रीकरण का अत्यधिक आभाव हैं अभी तक केवल 29ः कृषि क्षेत्र का ही यंत्रीकरण हो सका हैं।

;पपपद्ध भू.जोतों का अत्यधिक विखंडन और छितराव होने से कृषकों को कृषि प्रबंधन में काफी दिक्कते होती हैं।

;पअद्ध उन्नत कृषि औजार एवं यंत्रो के आभाव में तथाकथित अवैज्ञानिक यंत्रो से कृषि कार्य का सम्पादित होना।

;अद्ध कृषि बाजार की अनुपलब्धता

;अपद्ध कृषि साख की बड़े पैमाने पर अनुपलब्धता

;अपपद्ध किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियाशीलता में शिथिलता और किसानो में अशिक्षा के कारण इसका सिमित प्रयोग।

;अपपपद्ध कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलना।

1955.60 से आजतक फर्टिलाइज़र्स एवं अन्य कीटनाशक दवाईयों के मूल्य में 300ः की वृद्धि दर्ज की गयी हैं। सार्वजानिक क्षेत्र एवं सरकारी नौकरियों में नियुक्त कर्मियों का वेतन भाता आदि में सातवे वेतन निर्धारण समिति के अनुशंसा पर लगभग 350ः की वृद्धि की गयी जबकि कृषि उत्पादों के कीमत में कुल मिला कर 79ः की ही वृद्धि हो पायी हैं। ऐसी स्थिति में सीमांत एवं लघु किसानोंए भूमिहीन कृषि मजदूरों के समक्ष अपने.अपने पारिवारिक भरण.पोषण के लिए लाभप्रद नियोजन के खोज में प्रवजन की वृति अपनाने को विवश होना पड़ता हैं।

यो तो नवम्बर 2019 में ही कोरोना वायरस के संक्रमण की क्रिया प्रारंभ हो गयी थी। लेकिन भारत में यह मुख्य रूप से 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा के साथ और 25 मार्च 2020 से 16 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन के साथ सम्पूर्ण देश में लागु हुआ और गरीबए भूमिहीन श्रमिक परिवारों के समक्ष एक व्यापक त्रासदी के रूप में उपस्थित हुआ। इस व्यापक लॉक डाउन ने सम्पूर्ण देश के सभी बड़े शहरों के कल कारखानोए उत्पादन इकाईयों और व्यावसायिक घरानों के शटर को डाउन करवाकर श्रमिकों को घर वापसी को मजबूर कर दिया।

श्रमिकों के रिवर्स प्रवजन का बिहार अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा हैं। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान ;ळज्ञत।द्ध के अंतर्गत बिहार के 32 जिलों और उत्तरप्रदेश के 31 जिलों में लागु किया गया।

कुल 6ण्7 मिलियन में से 2ण्36 मिलियन बिहार में और 1ण्75 मिलियन न्च् में श्रमिकों की वापसी हुयी। 116 जिलों में औसतन 25000 श्रमिकों की वापसी हुयी। ळज्ञत। के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिकों को अपने गृह जिले में 125 दिनों का रोजगार दिलाने का प्रावधान किया गया हैं और इसके लिए 50ए000 करोड़ रूपये का आबंटन पहले ही किया गया हैं।

यह सत्य हैं कि बिहार रिवर्स प्रवजन से प्रभावित राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। जहाँ मजदूरों की वापसी इस आशा के साथ हुयी थी कि वे फिर लौटकर दूसरे शहरों और राज्यों में नहीं जायेंगे। लेकिन इन श्रमिकों को तुरंत काम में लगाना बिहार सरकार की जबाबदेही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया हैं कि हमें केंद्र से सहयोग की अपेक्षा नहीं हैं। हम अपने बदौलत इन श्रमिकों का नियोजन कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पायाए क्योंकि कम से कम दस जिलों में 25000 श्रमिकों कि वापसी के अनुमान के स्थान पर 1ए00ए000 श्रमिकों का आगमन हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा की गयी सभी सहयोगात्मक उपाय स्वतः नष्ट हो गये।

अनुभवी विद्वानों ;प्रो० अलख एन शर्माद्ध का मत हैं कि इस रिवर्स प्रवजन का बिहार अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव रहेगा और लम्बे समय तक श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा।

कारण स्पष्ट हैं रू.

' बिहार में कृषि नियोजन का सर्वाधिक संपन्न स्रोत है किन्तु कृषि क्षेत्र में सालोभर रोजगार की उपलब्धता संभव नहीं हैंए क्योंकि बिहार की कृषि मूलतः बर्षा आधारित हैं।

' यहां सामान्य स्थितियों में भी सभी श्रमिकों को काम नहीं मिल पता हैंए तभी तो वे प्रवजित होते हैं।

' अचानक 100000 श्रमिकों कि वापसी प्रत्येक जिले में ;पद्ध श्रमपूर्ति में अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया। ;पपद्ध श्रम आपूर्ति में वृद्धि . आपूर्ति वक्र में नीचे कि ओर विवर्तन से प्रदर्शित होता हैं। ;पपपद्ध जबकि बाढ़ और अन्य सम्पूर्ण लॉक डाउन से प्रभावित बिहार कृषि में श्रम के मांग में कमी हो गयी। क्योंकि लॉक डाउन के कारण कृषि उत्पादों ;अनाजए फलए सब्जीए मछलीए मुर्गाए अंडा आदिद्ध कि आपूर्ति स्थानीय स्तर पर होने लगी। बाहर की आपूर्ति बंद हो गयी। लागत कीमत में भी कमी होने लगी। परिणामस्वरूप किसानो द्वारा कृषि निवेश में कमी कर दी गयी।

इस प्रकार कृषि श्रमिकों कि मांग में कमी का प्रदर्शन श्रम मांग वक्र के ऊपर की ओर विवर्तन से होता हैं।

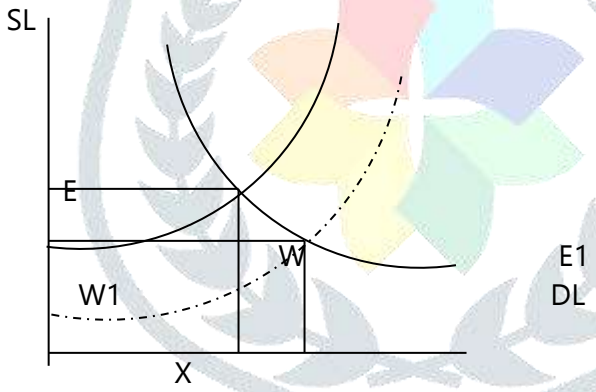

चित्र-1

प्रथमतः तो रिवर्स प्रवजन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों खासकर कृषि कार्य में संलग्न होने वाले श्रमिकों के आपूर्ति में वृद्धि में संतुलन मजदूरी दर ˇ से घटकर ˇ1 हो गया।

द्वितीयः कृषि उत्पादों के मांग में कमी और स्थानीय स्तर पर आपूर्ति में वृद्धि से तमाम कृषि उत्पादों के मूल्य में अप्रत्याशित कमी हो गयी। कृषकों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। परिणामतः कृषि निवेश में कमी करने के साथ साथ श्रम नियोजन की आवश्यकता भी घरेलु सदस्यों से होने लगी और श्रमिकों की मांग वक्र में नीचे की ओर विवर्तन होता हैं जिससे फिर संतुलन मजदूरी में और कमी होती है। जैसा की चित्र से स्पष्ट हैं इस प्रकार रिवर्स प्रवजन और लॉक डाउन के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक अवसाद की उत्पति हो गयी और सम्पूर्ण समाज ;नियोक्ता और नियोजितद्ध अनेको परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो गये। इस सभी कारणों के चलते हमारा ळक्च वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी।

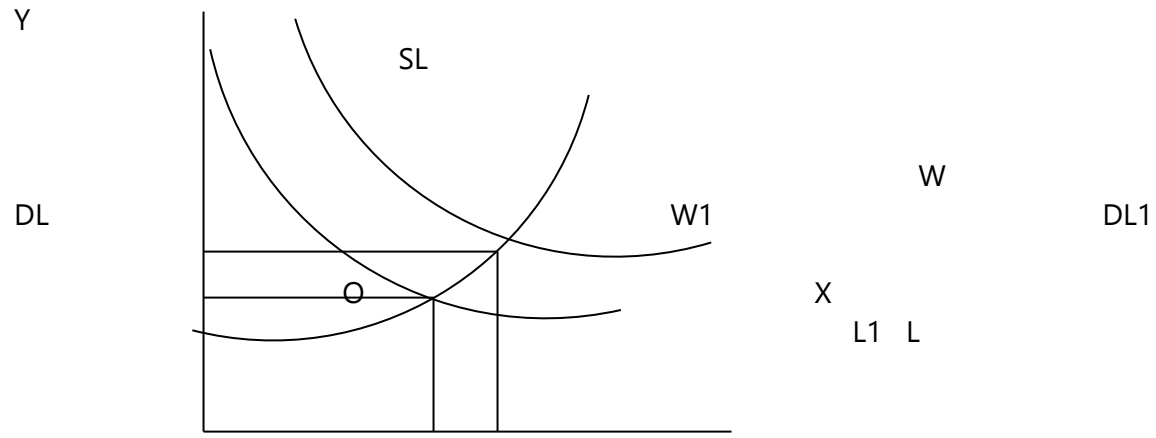

' बिहार में 11ण्3: और न्च में 22ण्28: न्तइंद आबादी हैं।

' बेरोजगारी दर 2017.18 में बिहार में 7ण्2: और न्च में 6ण्4: थीए जबकि राष्ट्रिय औसत 6ण्1: हैं।

' शहरीकरण का धीमा दरए अत्यधिक आबादी का दबाव और रोजगार के अवसर का सर्वथा आभाव यहाँ की आबादी को डपहतंजम करने को बाध्य करती हैं।

' भूमिहीनताए कृषि का मौसम पर आश्रित होनाए निम्न मजदूरी दरए बेरोजगारी आदि डपहतंजपवद के कुछ महत्वपूर्ण क्तपअमते हैं।

'जीम च्वेपजपअम जीपदहे रू ;पद्ध डपहतंजपवद ीमसचे चमवचसम जव इमबवउम मबवदवउपबंससल मउचवूमतमक बपजप्रमदेण

' ब्वअपक .19 ने इन श्रमिकों को अचानक गरीबी की जाल में फंसा दियाए क्योंकि इनके पास पर्याप्त अतिरेक साधन का आभाव हैं और ना ही इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का उपाय बचाव के लिए होता हैं।

' राहत सामग्री भी इन श्रमिकों के लिए सामान्यतया अपर्याप्त होता हैं।

' इनके बचाव के लिए तीन सिद्धांतों का प्रयोग होता हैं ;पद्ध सहायता ;पपद्ध सुरक्षा ;पपपद्ध सशक्तिकरण

अल्पकालिक सहयोग के रूप में इन प्रति प्रवजनित श्रमिकों को सहायता और सुरक्षा की जरूरत होती है।

' दीर्घकालिक सहायता के रूप में इन्हे सशक्तिकरण की जरूरत होती हैं।

' आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार न 5 ज्ञह. 1 ज्ञह दाल प्रति परिवार प्रतिमाह अगस्त तक देने की घोषणा की हैं।

' सरकार ने व्दम छंजपवदए व्दम त्ंजपवद की भी घोषणा की हैं।

' रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए मनरेगा में 40000 हजार करोड़ का आवंटन बढ़ाया गया हैं।

' गरीब कल्याण योजना प्रारम्भ किया गया हैं जिसमे पहले से चले आ रहे 50 योजनाओं को शामिल किया गया हैं। इसमें 50000 करोड़ के व्यय से रोजगार सृजन का प्रयास किया गया हैं। जो मनरेगा के माध्यम से ही संभव हो पाया हैं। अर्थात करोना वायरस के इस त्रासदी काल में मनरेगा प्रति.प्रवजित श्रमिकों के लिए जीवन रेखा के रूप में सामने आई।

च्ड३े बंसस जव चतवअपकम 93: ूवतामते`मसा.तिमसपंदज इल चतवअपकपदह `चचतवचतपंजम पिदंदबपंस `नचचवतजण

;पद्ध ग्रामीण विकास मंत्रालय ;पपद्ध पंचायती राज मंत्रालय ;पपपद्ध यातायात एवं उच्च राजमार्ग ;पअद्ध माइंस ;अद्ध पेयजल ;अपद्ध सेनिटेशन ;अपपद्ध पर्यावरण ;अपपपद्ध रेलवे ;पगद्ध नए एवं रइनोवेबुल ऊर्जा ;गद्ध सीमा सड़क ;गपद्ध टेलिकम और ;गपपद्धकृषि।

ब्वअपक .19 एवं ब्वउचसमजम स्वबाकवूद का प्रवजित एवं प्रति.प्रवजित श्रमिकों पर प्रभाव रू.

न्छप्ब्म् एवं क्मअमसवचउमदज डंदंहमउमदज प्देजपजनजम ;क्डप्द्ध के शोध निष्कर्षो के मुताबिक रू.

1ण 51: प्रति प्रवजित ;प्रवासीद्ध श्रमिक परिवारों ने पूर्णरूपेण अपना रोजी रोजगार और आय के सभी स्रोतों को खो दिया हैं।

2ण 30: परिवारों के आय का बड़ा हिस्सा ब्वअपक .19 और प्रति उत्पन्न सम्पूर्ण लॉक डाउन से समाप्त हो गया हैं।

3ण 12: श्रमिक परिवारों के आय का कुछ अंश छीन गया हैं।

4ण बाकि के 07: श्रमिक परिवार अपने ग्रामीण आधारभूत संरचना मजबूत होए के कारण अपनी स्थिति बनाये रखने में सक्षम हो पाए हैं।

उपाय ;त्मउमकपमेद्ध

निःसंदेह सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी मुश्तैदी और तत्परता से निर्वहन की हैंए किन्तु देशव्यापी समस्या और सम्पूर्ण देश में एक साथ इस समस्या के विस्तार ने राहत उपायों एवं प्रशासनिक प्रबंधों के सफल क्रियान्वयन में बाधा उतपन्न हुयी हैं।

' उतपन्न स्थितियों से निबटने के नियोजन में देर से कार्यारम्भ किया गया जिससे अफरातफरी हो गयी।

' सम्पूर्ण लॉक डाउन लागू करने से पूर्व श्रमिकों के पुनर्वास या पुनर्नियोजन की समस्या का न तो आकलन किया गया और न ही उसके समाधान का उपाय ढूंढा गया।

' ऐसा प्रतीत होता हैं की सरकार ने अचानक से सम्पूर्ण लॉक डाउन का निर्णय देश पर थोप दी।

' गंभीरता से विचार किया जाता तो सम्पूर्ण लॉक डाउन की जरूरत ही नहीं पड़ती।

' क्योंकि ब्वअपक.19 के फैलाव और संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते थे रू.

;पद्ध प्रत्येक औद्योगिक इकाईयों में आंतरिक लॉक डाउन लागु कर उस इकाई को कार्यस्थलोंए आवासीय स्थलों पर किसी भी प्रकार के गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दी जाती ।

;पपद्ध शहरों एवं गावों में उसके इकाई स्तर पर लॉक डाउन और आंतरिक स्तर पर मूवमेंट की छूट दी गयी होती।

;पपपद्ध कार्यालयों एवं संस्थानों को पूर्णतः लॉक कर कर्मियों को ऑनलाइन कार्य संपादन का आदेश निर्गत होता।

;पअद्ध बाजार के प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार थर्मल स्कैनिंग का पूर्णकालिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाता और किसी भी संदेह का यथोचित चिकिस्तीय प्रक्रिया अपनाने का प्रबंध किया गया होता।

;अद्ध प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में या तो ऑनलाइन अध्यापन का प्रबंध किया गया होता या फिर ऑफलाइन की स्थिति में थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध फुलप्रूफ के साथ किया गया होता।

' प्रत्येक कार्यस्थलों एवं आवासीय स्थलों ;शहरों मेंद्ध में विशिष्टता के साथ सम्पूर्ण सुविधा संपन्न कोरेन्टाईन सेण्टर एवं आइसोलेसन सेण्टर की स्थापना ट्रेंड मेडिकल टीम के साथ की गयी होती।

' सफाई कर्मियों को विशेष सुरक्षा कीटस एवं सहायता पैकेज के साथ पूर्ण सफाई का जिम्मा देकर समग्र रूप से स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन किया गया होता।

उपरोक्त उपाओं के अमल से न तो लॉक डाउन होता और तब फिर प्रति.प्रवजन की समस्या ही नहीं होती।

आवश्यक सुझाव रू.

' यदि श्रम शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में हैं तो फिर प्रत्येक राष्ट्र को अपने श्रम शक्ति का सही आकलन उसके विशिष्ट विन्यास के साथ होना चाहिए।

' यह तभी संभव हो सकता हैं जब हमारे पंचायती राज व्यस्था के न्यूनतम इकाई वार्ड स्तर पर श्रमिकों का`जंजने तमचवतज तैयार हो और प्रतिबर्ष इसको अद्यतन किया जाय।

' श्रमिकों के`जंजने त्मचवतज में उनके`ापसस डंचचपदहए च्संबमे वि क्मेजपदंजपवद और कार्य विवरण अंकित हो।

' उनके परिवार का विवरण भी स्पष्ट रूप से अंकित हो।

' ँतक स्मअमस से श्रम मंत्रालय तक एक बींददमस वि पदवितउंजपवद निर्मित हो ताकि इन श्रमिकों और उनके परिवार में घटित घटनाओं की सूचनाओं का आदान.प्रदान हो सके और ससमय यथोचित सहयोग उपलब्ध कराकर प्रभावित परिवार की क्षति को काम या समाप्त किया जा सके।

शोध सन्दर्भ

1ण दैनिक समाचार पत्र . हिंदुस्तानए प्रभात खबरए दैनिक जागरणए दैनिक भास्करए हिंदुस्तान टाइम्सए जनवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक की विविध प्रति

2ण विभिन्न आलेखों की प्रति जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ब्वअपक .19 और इसके प्रभाव पर लिखा गया

3ण आर्थिक सर्वे 2017.18ए 2018.19 और 2019.20

4ण भारत . 2017ए 2018ए 2019 एवं 2020

५ण विश्व स्वास्थ्य संगठन ;भ्ब्द्ध के ब्वअपक.19 से सम्बंधित रिपोर्ट

६ण प्राचीन भारत का इतिहास

७ण योजना कुरुक्षेत्रा आदि पत्रिकाओं की विविध प्रति ।